इकाई 13 संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

लक्ष्य और उद्देष्य

13.2 सुविधावंचित समूहों से भेदभाव

13.2.1 अफ्रीकी अमरीकी

13.3 अष्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन

13.4 नागरिक अधिकार आंदोलनों के परिणाम

13.4.1 मूल अमरीकी

13.4.2 हिस्पेनिक और एषियाई अमरीकी

13.4.3 महिलाएँ और नागरिक अधिकार आंदोलन

13.4.4 समलैंगिकों के अधिकार

13.5 डेमोक्रैट्स और नागरिक अधिकार

13.6 रिपब्लिकन्स और नागरिक अधिकार

13.7 सारांष

13.8 बोध प्रष्न

13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.1 प्रस्तावना

विष्व में नागरिक अधिकार आंदोलन पर महात्मा गाँधी का प्रभाव संदेहातीत है। असहयोग आन्दोलन और नागरिक अवज्ञा आन्दोलन के माध्यम से अहिंसक प्रतिरोध समाज के सुविधा प्राप्त वर्गों के विरुद्ध सुविधा वंचित वर्गों का शक्तिषाली उपाय है। गाँधी का प्रभाव विकसित पष्चिम की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कहीं अधिक दिखाई दिया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेता जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन अफ्रीकी लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अहिसंक नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, वे महात्मा गाँधी द्वारा अत्यधिक प्रेरित हुए थे।

नागरिक अधिकार देष के कानून के अधीन व्यक्तियों को समान संरक्षण और समाज में सार्वजनिक सुविधाओं तथा सेवाओं की समान सुलभता के लिए अधिकार निर्दिष्ट करने वाला आन्दोलन है। नागरिक स्वतंत्रता से नागरिक अधिकार भिन्न हैं। इसमें विशेष बात यह कि नागरिक स्वतंत्रता में भाषण और अभिव्यक्ति की तथा नागरिकों को अन्य स्वतंत्रताएँ अंतर्निहित हैं जिन्हें सरकार द्वारा संभावित उल्लंघन से संरक्षित किया जाता है। दूसरी ओर, नागरिक अधिकार का संबंध अलग–अलग सदस्यों या समूहों से होता है चाहे वे नस्लीय धार्मिक और अन्य हों – से संबंध रखते हैं, जिनके साथ सरकार द्वारा और कुछ सीमा तक निजी पार्टियों या अन्य द्वारा भी समान रूप से व्यवहार किया जाना आवष्यक है। इसको और अधिक साधारण शब्दों में व्यक्त करें तो, नागरिक स्वतंत्रता का संबंध केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है और नागरिक अधिकारों का संबंध समानता के मुद्दों से संबद्ध है।

लक्ष्य और उद्देष्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- नागरिक अधिकारों (civil rights) की संकल्पना का अर्थ और महत्व समझ सकेंगे;
- संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America - USA) में नागरिक अधिकारों के लिए किए गए आंदोलन को जान सकेंगे; और
- अधिकार सुनिष्चित करने में अंतर्निहित भिन्न–भिन्न समुदायों की भूमिका की समीक्षा कर सकेंगे।

13.2 सुविधावंचित समूहों से भेदभाव

संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन का इतिहास सब मिलाकर समानता के लिए व्यापक समूहों के दावे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सभी व्यक्तियों के विभिन्न अधिकारों को मान्यता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकारों का विधेयक व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति, भाषण, सभा, धर्म की पद्धति अपनाने आदि की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परंतु सभी अमरीकी इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में समर्थ नहीं हुए हैं। गणतंत्र के जन्म से संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न सुविधावंचित वर्गों को अन्य साथी नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए कई दषकों तक संघर्ष करना पड़ा था। अधिक स्पष्ट रूप से मूल अमरीकी, महिलाएँ, अफ्रीकी अमरीकी, हिस्पेनिक अमरीकी, एषियाई अमरीकी और बहुत सारे अनेकों अन्य को संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए लम्बे समय तक संघर्ष प्रारंभ करने तथा जारी रखने के लिए कड़े प्रयास करने पड़े।

बहुत लम्बे समय तक भेदभाव सहन के बाद ये समूह कानूनी शब्दों में कानून का समान संरक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं की समान सुलभता और मतदान का समान अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून नस्लीय, लिंग, नृजातीयता या धर्म के आधार पर अब व्यक्तियों से कोई भेदभाव नहीं करते हैं अर्थात वे सब पर समान रूप से लागू होते हैं। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार, विशेषकर सन् 1950 और सन् 1960 के दषकों के दौरान मुख्य रूप से अफ्रीकी अमरीकियों के उत्थान के लिए और उन्हें नागरिक अधिकारों से सम्पन्न करने के प्रयास थे। कानूनी समानता तब तक वस्तुतः समानता में मूर्त रूप नहीं लेती है, जब तक कि नागरिक अधिकार आंदोलन अपने लक्ष्यों में सफल नहीं होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि सुविधावंचित समूहों ने विरले ही संघर्ष के बिना कानूनी समानता प्राप्त की हो। शक्तिषाली समूह सदा सुविधावंचित समूहों को समानता के अधिकारों की अधिक मात्रा देने का लगातार प्रतिरोध करते रहे हैं।

13.2.1 अफ्रीकी अमरीकी

संविधान का निर्माण करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों और हज़ारों अफ्रीकी गुलाम थे। विष्व का सबसे पहला लिखित संविधान गुलामों को ऐसा मानव प्राणी नहीं मानता था जो श्वेत आबादी से समानता के लिए योग्यता रखते हों और उन्हें पूरी नागरिकता नहीं दी गई थी। सन् 1808 तक गुलामों के व्यापार की अनुमति थी। सामाजिक संस्थाओं के रूप में गुलामी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे भयंकर गृह युद्ध के बाद समाप्त की गई थी जिसने राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए संकट पैदा कर दिया था। गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की अवधि आई। जब सन् 1877 में पुनर्निर्माण समाप्त हुआ और गुलाम राज्यों से संघीय सैनिक हटाए गए, सामाजिक–राजनीतिक जीवन में श्वेत लोगों की श्रेष्ठता वापस लोट आई थी। दक्षिणी श्वेत जन संख्या या लोगों ने नस्लीय

पृथक्करण की पद्धति अपनाने के लिए नए नियम और विनियम अपनाए जिन्हें आमतौर पर जिम क्रो कानून कहा जाता है। अष्वेत लोगों को वैसी ही सार्वजनिक सुविधाएँ और षिक्षा संस्थाएँ शेयर करने से प्रतिबंधित किया गया था जैसी श्वेत समुदाय प्राप्त करते थे। अष्वेत बच्चों को पृथक विद्यालयों में पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता था जिनमें पर्याप्त आधारिक और सुविधाओं का नितान्त अभाव था। "अष्वेत उन होटलों और रेस्टोरेंटों में प्रवेष नहीं कर सकते थे जो ष्वेत लोगों के लिए थे"। नस्लीय पृथक्करण और भेदभाव सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में भी अपनाया जाता था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने जिम क्रो (Jim Crowe) कानूनों का समर्थन कर प्रमुख श्वेत समुदाय का पक्ष लिया। *प्लेसी (Plessy)* बनाम *फर्गूसन (Ferguson)* केस में सन् 1896 में संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दो नस्लों के लिए "पृथक" सुविधाएँ संविधान का उल्लंघन नहीं करती हैं जहाँ तक सुविधाएँ समान हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि संविधान नस्लीय समानता के बारे में थोड़ी ही समानता उपलब्ध कर सकता है, यदि एक नस्ल दूसरे नस्ल से घटिया अथवा निम्न हो।

अष्वेत समुदाय के नेताओं ने इस प्रकार के व्यवहार का कड़ा प्रतिरोध किया तथा कानूनी उपायों का सहारा लेकर नस्लीय भेदभाव और कट्टरता के विरुद्ध लगातार लड़ते रहे। परंतु सन् 1930 के दषक तक कानूनी तरीका बहुत कम राहत दे पाया था जब संयुक्त राज्य अमेरिका का उच्चतम न्यायालय ने संतुलित तरीके में अपनी राय बदली। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यदि अफ्रीकी अमरीकियों के लिए कोई सुविधाएँ नहीं हैं तो उन्हें श्वेत लोगों के लिए आरक्षित सुविधाएँ प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। दो दषकों के बाद एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने *प्लेसी सिद्धांत* और नियम को बदल दिया और *ब्राउन (Brown)* बनाम *बोर्ड ऑफ एजुकेषन ऑफ टोपेका (Board of Education of Topeka)* में निर्णय दिया कि पब्लिक स्कूलों के नस्लीय पृथक्करण करने से "अष्वेत बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न करते हैं कि समुदाय में उनकी क्या हैसियत है, वह उनके दिल और दिमाग में ऐसा बुरा प्रभाव डालता है जिसे कभी नहीं हटाया जा सकता है। पृथक शैक्षिक सुविधाएँ स्वाभाविक रूप से असमान हैं।" यह केस टोपेका, कैनसास में एक अष्वेत बच्चे, लिण्डा कारोल ब्राउन के लिए नेषनल एसोसिएषन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल (National Association for the Advancement of Coloured People - NAACP) द्वारा शुरु किया गया था जिसे आल व्हाइट ऐलिमेंटरी स्कूल में प्रवेष मना किया गया था। केस की ज़िरह थरगुड मार्षल द्वारा की गई थी जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का पहला अष्वेत न्यायाधीष बने थे।

ब्राउन निर्णय का दक्षिणी ष्वेत लोगों द्वारा स्वागत नहीं किया गया था। यहाँ तक कि उत्तर में रहने वाले श्वेत समुदाय के बहुत कम लोगों द्वारा इसको सराहा गया था। इस निर्णय के तीन वर्ष बाद लिटिल रॉक शहर में अष्वेत बच्चों को श्वेत पब्लिक स्कूलों में प्रवेष करने की इज़ाजत नहीं दी जाती थी परन्तु इसको लागू करने के लिए राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइज़नहॉवर द्वारा पृथक्करण पर ब्राउन निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए फेडरल नियंत्रण के अधीन अवकासस नेषनल गार्ड (ANG) रखे जाने के बाद ही समस्या का समाधान किया गया था।

यद्यपि, *ब्राउन* बनाम *बोर्ड ऑफ एजुकेषन ऑफ टोपेका* में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा सन् 1954 में पब्लिक स्कूलों को तकनीकी दृष्टि से वर्णभेद से मुक्त किया गया था, परंतु अभी भी पड़ोस में बहुत से स्कूल आवासन और नस्लीय पृथक्करण की असमानता के कारण वस्तुतः पृथक थे और स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि वे न केवल पृथक किए गए थे, बल्कि समान स्कूल "अंतर्निष्ठ रूप से असमान" थे, देष के बहुत से भागों में पब्लिक स्कूलों का नस्ल द्वारा पृथक करना जारी रहा। *स्वान* बनाम *शार्लोट मैक्लेनवर्ग बोर्ड ऑफ*

एजुकेषन (1971) में उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों के आगे एकीकरण के प्रयास में स्कूल पृथक्करण समाप्त करने के लिए बच्चों को बस द्वारा ले जाने (busing) की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।

सन् 1974 में संघीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि बौस्टन में स्कूलों का निर्माण किया गया था और नस्ल के आधार पर स्कूलों को पृथक करने के लिए जानबूझकर स्कूल जिला लाइनें खीचीं गई। सन् 1970 के दषक के प्रारंभ में न्यायालय के निर्णयों की शृंखला ने पाया कि नस्लीय दृष्टि से असंतुलित स्कूलों ने अल्पसंख्यक छात्रों के अधिकारों को कुचल दिया था। प्रतिकार के रूप में न्यायालय ने अलग–अलग शहरों में स्कूल जिलों के नस्लीय एकीकरण का आदेष दिया, कभी–कभी संपूर्ण रूप में जिले का संयोजन प्रतिबिम्बित करने के लिए जिले में प्रत्येक व्यष्टि स्कूलों का प्रजातीय एकीकरण करने का आदेष दिया। सामान्यतया, इसे स्कूल बस से जिले के भिन्न क्षेत्र में स्कूल में बच्चों को ले जाकर शिक्षा प्राप्त कराई गई थी। इस प्रयोग की व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में "बसिंग" (Busing) या "वर्गभेद समापन बसिंग" के रूप में उल्लेख किया जाने लगा था।

हालांकि बहुत से श्वेत परिवार अपने बच्चों को अपरिचित (और हिंसात्मक अष्वेत) पड़ोस में स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए काफी दूर स्कूलों में भेजने से बचने के लिए वे उपनगरों में चले गए और जो वहीं वहीं जाकर बस गए थे और उन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में भेजा। इसके परिणामस्वरूप, शहरी स्कूल अत्यधिक अष्वेत हो गए; इस प्रकार अनिवार्य बस परिवहन की प्रभाविकता घट गई। यद्यपि, *मिलिकन* बनाम *ब्रैडली* (1974) में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिलों के पार बच्चों का बस परिवहन असंवैधानिक है, बड़े शहरों की सीमा तक इसे सीमित किया परंतु इसमें संदेह नहीं है कि बस परिवहन ने नस्लीय अल्पसंख्यक स्कूली बच्चों को अधिक बड़े समुदाय से जोड़ा था। सन् 1980 के दषक से अलगाव या प्रथक्करण समाप्त करने वाला बस परिवहन घट रहा है।

13.3 अष्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन

उच्चतम न्यायालय के *ब्राउन निर्णय* के तत्काल बाद अफ्रीकी अमरीकी नेताओं ने समुदाय के नागरिक अधिकारों के लिए राजनीतिक आंदोलन करना आरंभ कर दिया था। इनमें सबसे अधिक परिचित नेता मार्टिन किंग लूथर जूनियर थे जिन्होंने अफ्रीकी अमरीकियों की सामाजिक–आर्थिक दशा को सुधारने और नागरिक अधिकारों को दिलाने के बारे में दबाव डालने के लिए अलबामा में शांतिपूर्ण मार्च और प्रदर्षनों का आयोजन लगातार किया। इस प्रकार के आंदोलनों ने अनेक कठिन बाधाओं और विरोधों का सामना किया था तथा इनका बहुधा निर्दयतापूर्वक दमन किया जाता था।

आंदोलन में सबसे अधिक ज्ञात घटनाओं में एक सन् 1963 में अलबामा में बर्मिंघम शहर में किंग द्वारा आयोजित आन्दोलन मार्च की थी। जैसे ही किंग और उनके समर्थकों ने अपना शान्तिपूर्ण मार्च और प्रदर्षन प्रारंभ किया, शेरिफ यूजीन "बुल" कार्नर के नेत्व में बर्मिंघम पुलिस ने किंग सहित प्रदर्षनकारियों पर "कुत्तों, पशुओं को आन्दोलन कारियों पर छोड़ दिए गए और अग्नि होज" से आक्रमण किया था। पूरे देष ने टेलीविजन पर इस दारुण और क्रूर दृष्य को देखा था। इन घटनाओं ने संघर्ष को जारी रखने के लिए अफ्रीकी अमरीकी समुदाय के साहस और वीरता को आगे चल कर और अधिक सहारा दिया और अफ्रीकी अमरीकियों के पक्ष के प्रति बहुत से श्वेत अमरीकियों की सहानुभूति अर्जित करली गई थी। उसी वर्ष में इसके फलस्वरूप 2 अगस्त को किंग और अन्य नेताओं ने अफ्रीकी अमरीकियों के लिए नौकरियों, स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए विषाल "मॉर्च ऑन वाषिंगटन" का आयोजन किया जिसमें एक–चौथाई मिलियन लोगों ने भाग लिया था। आदरणीय किंग ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि मेरे चार छोटे–छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में

रहेंगे जहाँ उनका आंकलन उनकी त्वचा के रंग से नहीं किया जाएगा बल्कि उनके द्वारा किए गए आचरण और चरित्र की मात्रा द्वारा किया जाएगा।"

इस मार्च ने आन्दोलन की नैतिक सफलता और राजनीतिक विजय दिलाई थी। सन् 1964 में रुढ़िवादियों और नस्लवादियों द्वारा खड़ी की गई बाधाओं और अवरोध खड़े करने के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने अफ्रीकी अमरीकियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सार्वजनिक सुविधाओं की समान सुलभता प्रदान करने और नस्ल के आधार पर नौकरियों में भेदभाव निषिद्ध करने के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। परंतु कानून बनाने से न तो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव स्वतः समाप्त होता है और न ही लोगों में नस्लीय श्रेष्ठता की भावना ही समाप्त होती है। हालांकि दक्षिणी राज्यों ने संघीय नागरिक अधिकार अधिनियमों को लागू न करने का नया तरीका निकालना शुरु किया। उदाहरण के लिए, वर्जिनिया ने उन श्वेत नागरिकों के कानूनी व्यय का भुगतान करने के लिए आयोग स्थापित किया जो नागरिक अधिकार उपायों के उल्लंघन के लिए न्यायालय में लाए गए थे। पूर्ववर्ती दास प्रभुत्व के राज्यों द्वारा ऐसी युक्तियों ने केवल अफ्रीकी अमरीकियों और अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के बारे में अधिक करने के लिए संघीय सरकार की भावना को सुदृढ़ किया। राष्ट्रपति लिंनडन बी जॉन्सन के सक्रिय नेतृत्व और प्रयासों से संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने सन् 1965 में चुनावों में प्रजातीय बाधाएँ समाप्त कर मतदान अधिकार अधिनियम पारित किया है।

13.4 नागरिक अधिकार आंदोलनों के परिणाम

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमरीकियों समुदायों के अलावा कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। परंतु किसी भी अन्य समूह ने राजनीतिक आंदोलन शुरु करने में सक्रियता नहीं दिखाई, जैसा कि अफ्रीकी अमरीकी समुदायों द्वारा आंदोलन आरंभ किए और लम्बे समय तक जारी रखे गए जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलनों की धुरी बन गए थे।

हालांकि जब नागरिक अधिकार आंदोलन को अपूर्व सफलता मिली और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस ने क्रमषः सन् 1964 और 1965 में नागरिक अधिकारों और मतदान अधिकारों से संबंधित कानून बनाए, तब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी रूप से नागरिक आंदोलनों और विधायी उपायों का या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हुआ। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्राप्त लाभ या प्रोत्साहन के कुछ उदाहरण देना महत्वपूर्ण है।

13.4.1 मूल अमरीकी

मूल अमरीकी संख्या लगभग दस मिलियन थी जब यूरोप से पहले श्वेत अधिवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पाँव रखा था। यूरोपीय अधिवासियों ने युद्ध, धोखा, कूटनीति और नस्लीय सफाई द्वारा मूल अमरीकी जनजातियों पर विजय प्राप्त की। सन् 1900 तक इसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मिलियन से भी कम मूल अमरीकी निवासी थे। अन्य अल्पसंख्यक समूहों की भाँति इस समुदाय को भी कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।

सन् 1950 के दषक में मूल अमरीकियों ने अमरीकी जीवन मुख्यधारा में उन्हें आत्मसात करने में सहायता करने के उद्देष्य से उन्हें शहरों में बसने की संघीय सरकार की नीति का विरोध किया। यह प्रतिरोध उन्हें अपनी पैतृक सम्पत्ति खोने के और शहरों में अनुकूलन में कठिनाइयों के भय से उत्पन्न हुआ था। यद्यपि यह नीति सन् 1961 में समाप्त की गई थी, परंतु नागरिक अधिकार पर संयुक्त राज्य

अमेरिका के आयोग ने रिपोर्ट दी कि मूल अमरीकियों में गरीबी और बंचन आम था। सन् 1960 के दषक के नागरिक अधिकार आंदोलन ने मूल अमरीकियों को छोड़ दिया था। परंतु उन्होंने निस्संदेह अपनी माँगें और समस्याएँ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। सन् 1960 के दषक के नागरिक अधिकार कानूनों ने कम से कम उन कानूनों पर अधिकारों का उपभोग करने के लिए अन्य अल्पसंख्यक समूहों को अवसर प्रदान किया जो पहले नहीं थे।

तृतीय विष्व के राष्ट्रवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वदेष में उत्पन्न नागरिक अधिकार आंदोलनों की प्रगति से प्रभावित मूल अमरीकी सक्रियतावाद ने सन् 1960 और 1970 के दषकों में वे आक्रामक हो गए थे। भूमि और जल अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए किए गए आंदोलनों की शृंखलाएँ इन दो दषकों में शुरु की गई थीं। अमरीकी इंडियन मूवमेंट (AIM), की स्थापना सन् 1968 में की गई थी मूल अमरीकी नागरिक अधिकार आंदोलन के संगठन की स्थापना स्पष्ट रूप से मूल अमरीकियों में आत्म निर्णय प्रोत्साहित करने और उनके संधि अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता स्थापित करने के लिए की गई थी। अनेक वर्षों के बाद इसने मूल अमरीकी संगठनों को सरकारी फंड प्राप्त करने में सहायता की और सीमान्तक, उपेक्षित और गरीबीग्रस्त शहरी मूल के अमरीकियों की सहायता की। इसी वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने ऐसा इंडियन्स नागरिक अधिकार विधेयक बनाया जिसमें अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के समान संवैधानिक गारंटियाँ प्रदान की गई थी। परंतु यह मूल अमरीकियों की वास्तविक षिकायतें कम नहीं कर पाया।

अफ्रीकी अमरीकियों से षिक्षा लेते हुए मूल अमरीकियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी में ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स को अपने अधिकार में ले लिया और बाद में दक्षिण डकोटा में गाँव का नियंत्रण लिया। यह घटना पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं थी क्योंकि मूल निवासियों ने गोलीबारी की थी।जब मार्षलों ने गोलियाँ चलाईं। परंतु शीघ्र ही घटना लोगों के और इस अल्पसंख्यक समूह की दुर्दषा शासक अभिजात वर्ग के ध्यान में आई और उन्हें प्रभावित करने वाले संघीय कार्यक्रमों पर इन लोगों को अधिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए सन् 1974 में एक अन्य कानून बनाया गया था।

यद्यपि मूल अमरीकी समूहों और सरकारी प्राधिकारियों के बीच विरोध का सामना इस अवधि के दौरान नैमित्तिक हुआ, फिर भी मुख्यधारा के अमरीकी मूल अमरीकियों की आवष्यकताओं और न्यायसंगत माँगों के प्रति निस्संदेह संवेदनषील थे। सरकार की सभी शाखाओं को मूल अमरीकियों के समान व्यवहार की माँगों की अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया गया जो लम्बे समय से विलम्बित थे।

13.4.2 हिस्पेनिक और एषियाई अमरीकी

सन् 1960 के दषक के नागरिक अधिकार आंदोलन मुख्य रूप से हिस्पेनिक अमरीकियों और एषियाई अमरीकियों के नागरिक अधिकारों की माँग करने में भी सहायक हुए। हिस्पेनिक लोगों की बहुत बड़ी संख्या काम की खोज़ में संयुक्त राज्य अमेरिका में आई थी। ये लैटिन अमेरिका में अपने अपने देषों में न तो वापस जा सके और नही उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो सकी थी। इन अवैध विदेषियों को अपने नियोक्ताओं और सामान्य रूप से समाज से भी बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह नागरिक अधिकार आंदोलनों की भावना तथा सन् 1960 के दषक के कानूनों/उपायों की भी भावना में था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने सन् 1986 में आप्रवासन सुधार और नियंत्रण अधिनियम पारित किया जिसने उन अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की थी जो पिछले पाँच वर्षों तक का निवास करने का प्रमाण दे सकते थे।

परंतु हिस्पेनिकों को उस भेदभाव के लिए दोष स्वयं शेयर करना पड़ा जिनका सामना उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में किया। वे न केवल अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते आए, बल्कि उनमें

से बहुतों ने अंग्रेज़ी सीखना और मुख्यधारा अमरीकी समाज में घुलना मिलना भी अस्वीकार किया था। उन्होंने हठ से देषीयता आंदोलन, अर्थात् ऑफिषियल इंगलिष मूवमेंट का उदय हुआ जिसका उद्देष्य अंग्रेज़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका की राजभाषा बनाना था और इसके फलस्वरूप तीन दषकों के अंदर आगे से अधिक राज्यों ने अंग्रेज़ी को अपनी राजभाषा घोषित किया। आज भी कार्य स्थानों में अंग्रेज़ी का प्रयोग अनिवार्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस में बिल विचाराधीन है जो नियोक्ताओं को कर्मचारियों द्वारा उनकी भाषा पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे बिना अंग्रेज़ी प्रयोग करने की माँग करने का अधिकार देता है।

एषियाई अमरीकी, विशेषकर चीनियों और जापानियों को जिन्हें कोयले की खानों और रेलरोड निर्माण मे ंकार्य करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लाया गया था, लोगों द्वारा खुले रूप में व्यक्त और शासक अभिजात द्वारा भी व्यक्त गंभीर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ कानूनों ने भी उनके विरुद्ध भेदभाव किया। उदाहरण के लिए, सन् 1921 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने आप्रवासन सीमित करने के लिए कानून बनाया और कोटा प्रणाली लागू की तो यूरोपियों की तुलना में एषियाइयों को बहुत कम कोटा मिला था। सन् 1960 के दषक में नागरिक अधिकार आंदोलनों के घरेलू वातावरण मे ंएक बार फिर एषियाई अमरीकी सन् 1965 के आप्रवासान अधिनियम से लाभान्वित हुए जिसमें उनके पक्ष में कोटा संतुलित करने का प्रयास किया गया जिनके साथ पहले भेदभाव हुआ था। बहुत बड़ी संख्या में एषियाइयों और लैटिन अमरीकियों ने उस अधिनियम के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेष किया। एषियाई अमरीकियों के अधिकार भी न्यायालय के निर्णयों और सन् 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियमों के द्वारा धीरे–धीरे बढ़ाए गए।

13.4.3 महिलाएँ और नागरिक अधिकार आंदोलन

संयुक्त राज्य अमेरिका में उपनिवेषी समय के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रयोग करने, सार्वजनिक पद धारण करने या ज्यूरी के रूप में कार्य करने से विवर्जित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने अमरीकी महिलाओं के प्रति भेदभाव बनाए रखा था। ब्रिटिष सामान्य कानून का संयुक्त राज्य अमेरिका पर इतना अधिक प्रभाव था कि देष में महिलाओं ने सामान्यतया विवाह के बाद अपनी पहचान ही खो दी थी और वे पतियों की सम्पत्ति समझी जाती थी। उन्हें अपने पति की अनुमति के बिना सम्पत्ति खरीदने, धारण करने या निपटान करने की अनुमति नहीं थी। यह भेदभाव उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी प्रतिबिम्बित हुआ था कि परपुरुष संबंध पति की सम्पत्ति के अधिकार का उल्लंघन था।

महिलाओं के अधिकारों की बदलती हुई प्रस्थिति दषकों द्वारा चलाए गए लम्बे आंदोलनों और संघर्षों के बाद आई और दासता–विरोधी सम्मेलन में भाग लेने से दो महिलाओं के विरोध की प्रतिक्रिया में सन् 1848 में अपने अधिकारों को बल देने के निमित्त सबसे पहला महिला सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। तबसे महिला आंदोलन पर्याप्त प्रबल रहे हैं। यद्यपि सफलता प्रायः काफी देर बाद मिली थी। प्रारंभ में महिला अधिकार आंदोलन दासता–विरोधी संघर्ष से निकटता से जुड़ा हुआ था जैसे दासता–विरोधी आंदोलन। जब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो गुलामों को मुक्त किया गया और मुक्त किए गए अफ्रीकी अमरीकियों को अधिकार देने के लिए कई संवैधानिक संषोधन किए गए। महिलाओं को इससे कुछ भी नहीं मिला। उदाहरण के लिए, संविधान के पंद्रहवें संषोधन ने घोषणा की कि व्यक्तियों के मतदान अधिकार नस्ल, या रंग के आधार पर कम नहीं किए जा सकते हैं परंतु संषोधन लिंग पर स्पष्ट रूप से मौन था।

अमरीकी लोकतंत्र के कार्य संचालन में महिलाओं के सषक्तीकरण के लिए संघर्ष जारी रहा और अंत में सन् 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का उन्नीसवाँ संषोधन किया गया जिससे "सेक्स

के कारण” या लिंगभेद से मतदान के अधिकार से वंचित करने से संयुक्त राज्य अमेरिका या राज्य सरकारों को रोका गया। इस संषोधन की पुष्टि ने अन्य माँगों की पूर्ति के लिए महिलाओं के अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया, जैसे पुरुषों से समान अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, वित्तीय ऋण में भेदभाव समाप्त करना और कार्यस्थलों में सेक्सुअल उत्पीड़न समाप्त करना। महिला आंदोलनों द्वारा दषकों तक किए गए प्रयासों के बाद इनमें से कुछ माँगें मानी गई हैं। जबकि सन् 1923 में महिलाओं को समान अधिकार सुनिष्चित करने के लिए संविधान में एक अन्य संषोधन लाने का प्रस्ताव किया गया था, यह केवल आधी शताब्दी बाद सन् 1973 में पूरा हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस ने समान अधिकार संषोधन स्वीकृत किया गया। परन्तु इसे भी अपेक्षित तीन–चौथाई राज्यों द्वारा उसके पुष्टिकरण के दौरान ही अस्वीकृत कर दिया गया था।

परंतु आंदोलन जारी रहा और समाज महिलाओं के प्रति दुराग्रही भेदभाव के बारे में धीरे–धीरे संवेदनषील होता हुआ चला गया था। कांग्रेस ने देष के विभिन्न भागों में नागरिक अधिकार आंदोलनों के समय सन् 1963 में समान वेतन अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम रोज़गार के कुछ प्रकारों के वेतन और मज़दूरी में लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करता था। सन् 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने संघीय सरकार के कार्यक्रमों के लिए अनुदानों के प्रषासन में लिंग भेदभाव को निषिद्ध किया है। सन् 1972 के षिक्षा संषोधन अधिनियम ने षिक्षा में लिंग भेदभाव को निषिद्ध किया और सन् 1974 के समान ऋण अधिनियम ने वित्तीय ऋण प्रदान करने में उसी प्रकार का भेदभाव समाप्त किया। यद्यपि महिलाओं को पर्याप्त लाभ हुआ परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी लिंग असमानता रहती है। सार्वजनिक पद, प्रबंधकीय पदों और उच्च पदों पर पदोन्नति में लिंग प्रतिनिधित्व अभी भी नगण्य है।

गर्भपात पर बहस से महिलाओं के अधिकारों ने नया आयाम प्राप्त किया जो डैमोक्रेटिक पार्टी द्वारा समर्थित नए आंदोलन के रूप में सन् 1970 के दषक में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ था, इसमें महिलाओं को उनकी सेक्सुअलटी और गर्भ धारण करने या समाप्त करने पर पूर्ण स्वतंत्रता की माँग की गई थी। सुरक्षित और वैध गर्भपात के लिए महिलाओं, विशेषकर अविवाहित महिलाओं के अधिकारों के महत्व पर प्रकाष डालते हुए यह आंदोलन “प्रो–चॉयस” आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। *रो* बनाम *वेड* (1973) में संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने गर्भपात के लिए महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार किया और *प्लानड पेरेंटहुड* बनाम *केसे* (1992) में इसकी पुष्टि की गई थी। बाद में अनेकत्व राय से मामले पर निर्णय हुआ और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भी गर्भपात अधिकार के मामले में न्यायपालिका बँटी हुई है।

प्रो–चॉयस आंदोलन को प्रो–चायस कार्यकर्त्ताओं और उनके पक्ष में न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध रुढ़िवादी प्रोटेस्टेंट समूह द्वारा समर्थित रोमन कैथोलिक चर्च से कठोर प्रतिक्रिया मिली। एक आंदोलन, प्रोलाइफ आंदोलन जोकि रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा स्पष्ट रूप से प्रायोजित आंदोलन का गर्भपात के विरोध में खड़ा हुआ था। डैमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जिसमें बहुत से सदस्य रोमन कैथोलिक हैं कुछ ने, प्रक्रिया को अवैध बनाने तथा *रो* बनाम *वेड* के बदले बिना गर्भपात दर कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में विधायन भी प्रायोजित किया था। परंतु कंज़रवेटिवों ने इस आधार पर तब भी गर्भपात का विरोध किया कि विकसित भ्रूण एक व्यक्ति है और उन्हें जीने का अधिकार है और ये केवल प्रारंभिक गर्भपात (गर्भधारण के बाद पहले दो ट्राइमेस्टर के दौरान) और विलम्ब गर्भपात जब यह कौटाम्बिक व्याभिचार या बलात्कार के कारण हो, स्वीकारते हैं। कंजरवेटिव की माँग पर गर्भपात को समाप्त करना चाहते हैं।

13.4.4 समलैंगिकों के अधिकार

यद्यपि सहमत वयस्कों के बीच निजी समलिंगी कार्यों को ग़ैर–अपराधन मानने वाला सन् 1962 में पहला संयुक्त राज्य अमरीकी राज्य इलिनॉइस बना, गे (Gay) अधिकारों के लिए आंदोलन को जून 1969 में गति मिली जब न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में गे बॉर स्टोनवाल इन के संरक्षकों ने पुलिस के साथ तीन दिन तक संघर्ष किया जब पुलिस ने उसके परिसरों में छापा मारा। स्टोवेल विद्रोह ने गे अधिकार आंदोलन को समान अधिकारों और सामाजिक स्वीकृति के लिए एक व्यापक विरोध में बदल दिया।

सन् 1973 में अमरीकी मनोचिकित्सक संघ ने मानसिक विकृति की अपनी आधिकारिक सूची से समलैंगिकता को हटा दिया। उस समय तक यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत फैल चुकी थी। सन् 1982 में विस्कॉसिन ने इतिहास रचा जब यह सैक्सुअल अभिमुखता के आधार पर भेदभाव समाप्त करने वाला पहला राज्य बना।

इसका विजयी क्षण तब आया जब यू.एस. की सेना ने सन् 1993 में सेना में कार्य करने के लिए गेज़ को अनुमति दी, परंतु सेवा के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। यद्यपि, यह स्पष्ट विजय नहीं थी क्योंकि यह अभी भी सेवारत गे और स्त्रीसमलिंगी (lesbian) युगलों के बीच समलिंगी क्रियाकलाप को प्रतिबंधित करती थी। फिर भी इसने गे समुदाय के लिए सेना के दरवाज़े खोल दिए थे। इस नीति के अधीन जो बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल के दौरान बनाया गया और "पूछो नहीं, कहो नहीं" नाम से जानी गई, गे और स्त्रीसमलिंगी (lesbian) युगलों को सेना में सेवा से निकाला जा सकता था, यदि उन्होंने या तो गे होना स्वीकार किया या सेवा के दौरान इसमें शामिल हुए परंतु सेना को उनके सेक्सुअल अभिमुखता के बारे में पूछना निषिद्ध किया गया था।

सन् 2000 में, वरमौंट गे (gay) और स्त्रीसमलिंगी (lesbian) युगलों के बीच समान सेक्स विवाह या सिविल यूनियन को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना और सिविल यूनियनों के समान पति–पत्नी के रूप में समान लाभ, सुविधाएँ और उत्तरदायित्व प्रदान किए। परंतु ऐसे यूनियनों के "विवाह" के रूप में उल्लेख करने से परहेज़ किया गया और इतरलिंगकामी यूनियन शब्द का प्रयोग किया था। सन् 2004 में मैसाच्यूसेट्स में, सन् 2005 में कौनेक्टिकट में और सन् 2006 में न्यू जर्सी में कंज़र्वेटिवों के विरोध के बावजूद समलिंगी विवाह वैध बनाए गए।

सन् 2004 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान और फिर सन् 2006 में पुनः राष्ट्रपति जार्ज़ डब्ल्यू ब्रुष सिविल यूनियन के विरुद्ध बहुत सख्ती से आए और ज़ोर दिया कि विवाह विष्वास सम्मत और समय परखी प्रथा है जो पुरुष और महिला के बीच औपचारिक रूप से होती है। उन्होंने विशिष्ट रूप से पुरुष और महिला के बीच विवाह परिभाषित करने के लिए संघीय संविधान संषोधन करने और गे विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिपब्लिकन संगठन, क्रिष्चियन गठबंधन के प्रस्ताव का समर्थन किया। राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा कि संयुक्त राज्य अमरीकी सरकार विवाह को "मान्यता और सुरक्षा" देगी क्योंकि यह बच्चों के कल्याण और समाज की मज़बूती को बढ़ाता है।

दिलचस्प बात यह है कि यद्यपि मई 2008 में कैलिफोर्निया उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि समलिंगी (lesbian) युगलों को विवाह करने का अधिकार है। नवम्बर निर्वाचन के दौरान राज्य में मतदाताओं द्वारा एक पहल की पुष्टि हुई जिसे प्रस्ताव 8 कहा गया – जिसने समलिंगी विवाहों को निषिद्ध किया। इसी प्रकार एरिजोना और फ्लोरिडा में भी मतदाताओं द्वारा समलिंगी विवाहों को निषिद्ध करने का अनुमोदन किया गया। ऐराकांसास में मतदाताओं ने उन उपायों का अनुमोदन किया जोकि गे (gay) और स्त्रीसमलिंगी (lesbian) युगलों के बच्चे दत्तक ग्रहण करने को वर्जित करते थे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य नागरिक अधिकार मुद्दों की भाँति गे अधिकारों ने भी अमरीकी समाज को विभाजित किया है। गर्भपात की भाँति गे अधिकार मुद्दे ने अनम्य राजनीतिक ध्रुवीकरण उत्पन्न किया है। नवम्बर 2008 निर्वाचन के प्रतिक्षेप के बाद भी ईओवा उच्चतम न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2009 को समलिंगी विवाह प्रतिबंधकारी राज्य कानून रद्द कर दिया। एक सप्ताह से भी कम समय बाद वरमौंट विधानमंडल ने बिल पर गवर्नर के वीटो रद्द करते हुए समलिंगी विवाह को वैध बनाया।

13.5 डेमोक्रैट्स और नागरिक अधिकार

डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने आपको सदा नागरिक अधिकार आंदोलन में सबसे आगे रखा है। नागरिक अधिकार अधिनियम (1964) और मतदान अधिकार अधिनियम (1965), दोनों ही सबसे अधिक प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक, राष्ट्रपति लिंडन वी. जॉन्सन की पहल पर पारित किए गए थे। इन दो उपायों से अष्वेतों द्वारा राजनीतिक सहभागिता सार्थक हो गई और पूरे संयुक्त राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ठोस और अटल मतदाता ब्लाक बन गए। अब वे बड़ी संख्या में निर्वाचित राजनीतिक पद पर हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बाराक हुसैन ओबामा का संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करना है। यह कहने की आवष्यकता नहीं है कि ये अष्वेत नेता बहुत अधिक संख्या में डेमोक्रेट थे।

सन् 2004 में डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म ने संघीय संविधान संषोधित कर गे विवाह पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया और यह चाहता था कि विवाह राज्य स्तर पर परिभाषित किया जाए। डेमोक्रेट के लिए परंपरागत परिवारों के रूप में समान उत्तरदायित्वों, लाभों और संरक्षणों के साथ राष्ट्रीय जीवन में गे (gay) और स्त्रीसमलिंगी (lesbian) युगलों का पूरा समावेष उच्च प्राथमिकता है।

डेमोक्रेटों ने हिस्पेनिक वफादारी भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की है और उनके मतों का बहुत बड़ा हिस्सा भी भाषायी अल्पसंख्यकों को यह विष्वास देकर किया की शासकीय अंग्रेज़ी कुछ नहीं है बल्कि अंग्रेज़ी भाषा है और यह कि, आंदोलन के प्रस्तावक संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेज़ी से इतर भाषाओं का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। केवल अंग्रेज़ी के स्थान पर डेमोक्रेट्स ने अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी में प्रवीणता और दूसरी भाषा या बहुत भाषाओं के उद्देष्य से समर्थन दिया था। उनका मानना था कि उन लोगों को ध्यान में रखकर नागरिकों को अंग्रेज़ी से भिन्न भाषाओं में सार्वजनिक सुविधाएँ, कार्यक्रम और सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए जो अंग्रेज़ी में प्रवीण नहीं हैं। परंतु डेमोक्रेट इसमें अपेक्षाकृत असफल रहे हैं क्योंकि बहुत से डेमोक्रेट गवर्नरों (अराकनसास के बिल क्लिंटन सहित) ने अपने–अपने राज्यों की राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी घोषणा करने के उपायों पर हस्ताक्षर किए थे। फिर भी डेमोक्रेट द्विभाषी षिक्षा के लिए अपने समर्थन पर दृढ़ रहे हैं (पहले 1968 में प्रस्तुत और बाद में संषोधित) – जो आज कुछ नहीं हैं बल्कि "मैंटेनेंस" द्विभाषी षिक्षा और न कि "ट्राज़िष्नल" द्विभाषी षिक्षा है – और बहुभाषी मतपत्रों (मतदान अधिकार अधिनियम, 1965 द्वारा लागू) ने न केवल हिस्पेनिकों को कम मज़दूरी के कार्य लेने के लिए बाध्य किया, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया में किसी भी सार्थक सहभागिता से उन्हें और अन्य भाषीय अल्पसंख्यकों को परे रखा है।

डेमोक्रेट सदा गर्भपात के मामले में प्रो–चायस रहे हैं, सन् 2000 और 2004 दोनों मंचों ने *रो* बनाम *वेड* (1973) के अनुसार "प्रत्येक महिला को इसके चुनने का अधिकार" को मानने और सम्मान करने तथा गर्भपात को "सुरक्षित, कानूनी और विरला" बनाने की माँग को वास्तव में पार्टी विष्वास करती है कि महिला का "चुनने का अधिकार" संविधानिक स्वतंत्रता की और न्यायालयों द्वारा स्वीकार तथा संरक्षित करना आवष्यक है।

13.6 रिपब्लिकन्स और नागरिक अधिकार

यह बड़ी विडम्बना है कि इलिनॉइस के अब्राहम लिंकन, रिपब्लिकन राष्ट्रपति के हाथों दासता उन्मूलन के बावजूद आज व्यापक निर्वाचक समर्थन के लिए रिपब्लिक पार्टी अफ्रीकी–अमरीकी की ओर नहीं देख सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी को अष्वेतों का समर्थन इस तथ्य का प्रमाण है कि उन्होंने सामाजिक विमुक्ति की अपेक्षा राजनीतिक सषक्तीकरण को अधिक महत्व दिया है। यह अधिक क्षुब्धकारी तथ्य है कि अष्वेत समुदाय के नेताओं ने रिपब्लिकनों को नस्लवादी के रूप में चित्रित किया है और उदारवादी राय ने किसी न किसी प्रकार बहुधा श्वेत प्रभुत्ववादी कू क्लक्स क्लान को विशिष्ट रिपब्लिकनों से जोड़ने का प्रयास किया है। यह सत्य है कि न तो रिपब्लिकन नेताओं और न समग्र रूप में पार्टी ने अपने आपको अष्वेत नागरिक आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में पाया है। समान रूप से यह तथ्य भी सत्य है कि रिपब्लिकनों को उनके दासता विरोधी अवस्थिति के लिए क्लान द्वारा परंपरागत रूप से लक्ष्य किया।

रिपब्लिकनों ने परिवार के मूल्यों को धारण कर घरेलू मुद्दों का सार भाग बनाया है, इसी लिए वे प्रत्येक चुनाव में सदा प्रमुख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के छोटे कस्बे भी बहुत धार्मिक हैं और रिपब्लिकनों ने बहुधा समलैंगिकता और एक ही सेक्स के विवाहों को परंपरागत परिवार पर आक्रमण के रूप में चर्च के विरोध का समर्थन किया है और स्पष्ट किया है। ऐसा करने से उन्होंने सामाजिक रूप से कठोर रुढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल होने की ख्याति अर्जित की है।

रिपब्लिकन पार्टी के वर्षों पुराने पारिवारिक मूल्यों का समर्थन और उनसे पहचान ने भी इसे गर्भपात और प्रो–चॉयस सक्रियतावाद के विरोध में खड़ा किया था। उसके सन् 2000 और सन् 2004, दोनों प्लेटफॉर्मों में पार्टी ने गर्भपात के लिए अपने कठोर विरोध की आवाज उठाई और स्वीकार किया कि अजन्मे षिषु को "जीवन का व्यक्तिगत मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है" और गर्भपात करने के लिए सार्वजनिक राजस्व के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा उन संगठनों को फंड देना बंद करने की माँग की जोकि गर्भपात का समर्थन करते थे।। नवम्बर 2003 में राष्ट्रपति जॉर्ज़ डब्ल्यू बुष ने आंषिक जन्म गर्भपात प्रतिबंध अधिनियम – दीर्घकालिक गर्भपात निषेध करने के उपाय पर हस्ताक्षर किए और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने *गोंज़ाले* बनाम *कारहर्ट* (2007) में अपने निर्णय में अधिनियम की संवैधानिकता को स्वीकार किया था। निस्संदेह, रिपब्लिकन के गर्भपात पर रुख ने प्रो–चाइस और उदारवादी महिलाओं में उनकी पार्टी की कोई लोकप्रियता नहीं बनाई थी।

रिपब्लिकन पार्टी ने "अनुरक्षण" द्विभाषी षिक्षा का भी परंपरागत रूप से विरोध किया है – मूल भाषा के माध्यम से द्विभाषी षिक्षा के लिए सार्वजनिक निधि के प्रयोग पर – जो अंततः उन्हें अंग्रेज़ी सिखाने के बदले भाषायी अल्प जाति के छात्रों की भाषा बनाए रखने पर समाप्त हुआ – और ऐसी "ट्रांजिष्नल" द्विभाषी षिक्षा के प्रयोग का समर्थन किया जिसका उद्देष्य यथासंभव शीघ्रातिषीघ्र सभी अंग्रेज़ी कक्षाओं में भाषायी अल्पसंख्यक छात्रों को विषय सामग्री पाठ्यक्रमों का षिक्षण देना था। वैयक्तिक रूप से रिपब्लिकन्स शासकीय अंग्रेज़ी आंदोलन की अग्रिम पंक्ति पर रहे हैं और यह रिपब्लिकन का 104वाँ कांग्रेस में था कि सबसे पहला अंग्रेज़ी भाषा संषोधन, (ELA) एच. आर. 123 – बिल एमर्सन अंग्रेज़ी भाषा सषक्तीकरण अधिनियम, 1966) – जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की राजभाषा अंग्रेज़ी घोषित करने के लिए संघीय संविधान संषोधन करने की माँग की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया था। आज तक जिन्होंने सफलता की भिन्न–भिन्न मात्रा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में अंग्रेज़ी भाषा संषोधन प्रस्तुत किए हैं, वे सभी रिपब्लिकन हैं या रिपब्लिकनों ने बहुभाषी मतदानपत्र और मतदाता सहायता समाप्त करने की माँग भी बार–बार की। इस प्रकार देषीयता, आप्रवासी विरोधी और हिस्पेनिक विरोधी होने का आरोप अर्जित किया।

13.7 सारांष

संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्यंत्र की भाँति समूह अधिकारों को मानने के लिए नागरिक आंदोलनों का उदय हुआ। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका सांविधनिक दृष्टि से एक बहुसांस्कृतिक देष नहीं है, या फिर भी नागरिक अधिकार आंदोलनों ने चाहे अष्वेतों, गे का हो या आप्रवासियों का हों – इस प्रकार उन्होंने अमरीकी समाज में विभिन्न सीमांतक समूहों के सांविधानिक अधिकारों के सुरक्षण और संरक्षण सुनिष्चित किया है। राजनीतिक करेक्टनेस के युग का उद्घाटन हुआ जिसमें अष्वेत अफ्रीकी–अमरीकी, गृहणियाँ गृह–निर्माता, समलैंगिकता को वैकल्पिक सेक्सुअलिटी कहा गया और आप्रवासी योजक अमरीकी हुए।

नागरिक अधिकारों के संरक्षण के परिणाम में नस्लीय, लिंग और नृजातीय भेदभाव के निजी और सार्वजनिक कार्यों के उन्मूलन द्वारा नागरिक स्वतंत्रता का सफल प्रयोग हुआ है। इसका श्रेय नागरिक अधिकार आंदोलन को जाता है कि कोई भी समूह जो राज्य की ओर से या अन्य समूहों की ओर से भेदभाव अनुभव करता है, न्यायालय से उपचारी कार्रवाई की आषा कर सकता है, यदि सदा कार्यपालिका या विधायिका से नहीं होता है।

परंतु जैसे–जैसे आंदोलन का विस्तार होता है, नए समूह अस्तित्व में आते हैं और समूह को मान्यता दिलाने के लिए नए अधिकार बनाए जाते हैं और उन अधिकारों की संवैधानिकता पर निर्णय होते हैं जिन्हें यह संरक्षित या स्वीकार करने का प्रयास करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकारों का इतिहास बहुत रोचक है, यद्यपि यह सदा उग्र नहीं रहा है। अमरीकी राजनीतिक प्रणाली ने नागरिक अधिकार कार्यकर्त्ताओं को जगह दी और बड़ी पार्टियों के मंचों में उनके एजेण्डों को भी शामिल किया गया है। जनमत संग्रह, पहल, विधायन और न्यायालय निर्णय, सभी या तो उनके समर्थन में या विरोध में नागरिक अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा उठाए गए हैं।

परंतु इसमें संदेह नहीं है कि नागरिक अधिकार आंदोलनों ने अमरीकी राजनीति और समाज को गहराई से विभाजित किया है। दो प्रमुख दलों के घरेलू नीति प्लेटफॉर्म नागरिक अधिकारों के मुद्दों पर अपने–अपने दृष्टिकोण से काफी सीमा तक निर्धारित किए गए हैं। चर्च, जोकि अमरीकी मध्यम वर्गों के केन्द्र हैं, नस्लीयता, सेक्सुअल झुकाव (विशेषकर पादरियों के) और गर्भपात के मुद्दों से टूटे हुए हैं। यद्यपि नस्लीय दंगे अब आम नहीं हैं, नस्लीय दृष्टि से प्रेरित घृणात्मक अपराधों में तेज़ वृद्धि देखी गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की भाँति कहीं भी नागरिक अधिकार आंदोलन इतने सफल नहीं हुए हैं जितने यहाँ हुए हैं। यदि अन्यत्र इसी प्रकार के आंदोलन हुए हैं, तो यह शहरीकरण, औद्योगिकीकरण या आधुनिकीकरण के उपाय के रूप में हो सकते हैं (उदाहरण के लिए भारत में गे अधिकार आंदोलन शहरों में हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं) यह ग़ैर–अमरीकी समाजों में विकास की मात्रा समझने में अमरीकी नागरिक अधिकारों का धनात्मक योगदान रहा है।

13.8 बोध प्रष्न

1) आप “नागरिक अधिकारों” से क्या समझते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे सुविधावंचित समूह कौन से हैं जिन्होंने उस देष में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किए हैं?

2) सन् 1960 के दषक में अष्वेत नागरिक अधिकार आंदोलनों के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखिए।

3) संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलनों से कुछ सीमा तक मूल अमरीकी, एषियाई अमरीकी और महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

4) नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर आज अमरीकी राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति है?

13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) सी.ए. बार्नस, *जर्नी फ्रॉम जिम क्रो: दि डिसग्रीगेषन ऑफ सर्थन ट्रासिंट,* कोलाम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1983

2) थॉमस जेंटिल, *मार्च ऑन वाषिंगटनः अगस्त 28, 1963,* न्यू डे पब्लिकेषन्स, 1963

3) पीटर लेवी, *डॉक्यूमेंटरी हिस्ट्री ऑफ द मार्डन सिविल राइट्स मूवमेंट,* ग्रीनवुड प्रेस, 1992

4) अगस्त मायर, एवं एलियट रुडविक, *कोरः ए स्टडी इन द सिविल राइट्स मूवमेंट 1942–1968,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1973

5) मिखाल आर. बेलनैप, (संपा.), *सिविल राइट्स, द व्हाइट हाउस, एंड द जस्टिस डिपार्टमेंटः सिक्योरिंग द इनएक्टमेंट ऑफ सिविल राइट्स लेजिस्लेषन,* गारलैंड पब्लिषिंग, 1991

6) पाल मररे, *सिविल राइट्स मूवमेंटः रेफ्रेरन्सस एंड रिर्सोर्सेस,* मैकमिलन रेफ्ररेन्स, 1993

7) रोडा, ब्लमबर्ग, *सिविल राइट्सः द 1960ज़ फ्रीडम स्ट्रगल,* मैकमिलन, 1991

8) अगस्त मायर, जोन ब्रासी जूनियर, एलायट रुडविक, (संपा.), *ब्लैक प्रोटेस्ट इन द सिक्सटीज,* मार्कस वायनर पब्लिषिंग, 1991

9) विक्की क्रॉफोर्ड, *विमैन इन द सिविल राइट्स मूवमेंट, ट्रेलब्लेज़र्स एंड टॉर्चबिरियर्स,* इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1991

10) डेविस डब्ल्यू होक एवं डेविड ई., *विमैन एंड द सिविल राइट्स मूवमेंट,* 1954–1965, डिक्सन यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिस्सीसिपी, 2009

11) एडम फैयरक्लोह, मार्टिन लूथर किंग, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया प्रेस, 1995